



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/पौष 17, 1905
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/ PAUSA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 11 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/84:—
भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं० का० आ० 266 (अ)/18क/आई० डी० आर०
ए०/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा सैसर्स इंचेक-टायर्स
लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण
पांच वर्ष की अवधि के लिए, 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें
यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था;

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 289
(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83, तारीख 12 अप्रैल,
1983 तथा का० आ० 726 (अ)/18क/आई० डी०
आर० ए०/83, तारीख 11 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त
आदेश को 12 जनवरी, 1984 तक की और अवधि के लिए
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित किया गया
था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में
यह समीचीन है कि उक्त आदेश की अवधि 30 जून, 1984
तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि
के लिए बना रहना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन)
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की
उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 30 जून,
1984 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए जिसमें यह तारीख
भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० 2(20)/80-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDERS

New Delhi, the 7th January, 1984

S.O. 11(E)/18A/IDRA/84.—Whereas by the
Order of the Government of India in the Ministry
of Industry (Department of Industrial Develop-
ment) No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78, dated the

13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta, has been taken over for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983;

And, whereas by the orders of the Government of India No. S.O. 289(E)|18A|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, and S.O. 726(E)|18A|IDRA|83, dated the 11th October, 1983, the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 12th January, 1984;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[F. No. 2(20)|80-CUS]

का० आ० 12(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/84 :—
केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 411(अ)/18-चख/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 27 जून, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) का प्रवर्तन जिनका मैसर्स इंचेक-टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोदभूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि को 12 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और विस्तारित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 30 जून, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, को और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि को 30 जून, 1984 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए बढ़ाती है।

[का० सं० 2 (20)/80-सी०यू०एच०]

ए० पी० सरवान, संयुक्त सचिव

S.O. 12(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 411(E)|18FB|IDRA|78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 12th January, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order for a further period upto and inclusive of the 30th June 1984.

[F. No. 2(20)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.